BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 3, Issue 2, April-June, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

भारत में आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार के अवसर – चुनौतियां एवं संभावनाएं

वरुण प्रसाद सेमवाल

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय पी0 जी0 कॉलेज साहिया,

देहरादून, उत्तराखण्ड

सारांश – भारत युवाओं का देश है। भारत की 15 – 64 वर्ष की 67.8 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसलिए भारत की जनांकिकीय लाभांश की स्थिति प्राप्त है। जनांकिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए यह सर्वतः माना जाता है। की जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम 18 प्रतिशत है। पीएलएफएस 2023–24 के अनुसार, कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रणी बना हुआ है, जिसका हिस्सा 2017–18 में 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 46.1 प्रतिशत हो गया है। रोजगार में उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जिसमें विनिर्माण 12.1 प्रतिशत से 11.4 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 31.1 प्रतिशत से घटकर 29.7 प्रतिशत हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र भारतीय श्रम बल को आज भी खपाने में असमर्थ है। भारत में रोजगार में वृद्धि एवं जी.डी.पी. में वृद्धि के बीच विपरीत संबंध देखने को मिला है।

शब्द कुंजी– आर्थिक समृद्धि, जॉब्लेस ग्रोथ, समावेशी विकास, जनांकिकिय लाभांश, मानव विकास, ट्रिकल डाउन थ्योरी, फिलिप्स वक्र।

प्रस्तावना – आर्थिक विकास और समृद्धि के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा और गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि आर्थिक विकास किस तरह से लोगों तक सतत् रूप से पहुंचता है। आर्थिक विकास किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि से है। मीर एवं राउच के अनुसार, मात्रात्मक आर्थिक प्रगति ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। भारत में पिछले कई वर्षों से आर्थिक प्रगति की है। 1980–81 से 1990–91 के दौरान भारत की आर्थिक समृद्धि दर 5.2 प्रतिशत थी, जो सुधार काल के उपरांत 1990–91 से 2000–2001 के दौरान 5.6 प्रतिशत रही। जो तीव्र गति से बढ़कर 2004–05 से 2009–10 के बीच 8.7 प्रतिशत हो गई, जबकि वर्ष 2017–18 में 7 प्रतिशत हो गई 2019–20 में 4.2 प्रतिशत व 2020–21 में –7.3 प्रतिशत के गिरावट के बाद तीव्र गति से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 9.2 प्रतिशत हो गई। आर्थिक समीक्षा 2023–24 के अनुसार, भारत की जी.डी.पी. ग्रोथ वर्ष 2022–23 में 7 प्रतिशत 2023–24 में 7.8 प्रतिशत के वृद्धि के बाद वर्ष 2024–25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 से 7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। बेरोजगारी से आश्य उस श्रम शाक्ति से है जो काम करने के इच्छुक है काम करना चाहते हैं काम ढूंढने का प्रयास करते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है वास्तव में भारत मैं अदृश्य बेराजगारी की स्थिति पाई जाती है। जिसमें श्रम शक्ति काम में लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। भारत में जिस गति से जी.डी.पी. में वृद्धि हुई है, उसका अनुशरण रोजगार में वृद्धि से नहीं किया है। जबकि ट्रिकल डाउन थ्योरी के अनुसार, यदि जी.डी.पी. बढ़ती है तो उसके प्रभाव के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी आती है।

शोध के उद्देश्य–

1. भारत में आर्थिक समृद्धि एवं रोजगार के बीच संबंध ज्ञात करना।
2. रोजगार में कृषि, उद्ययोग एवं सेवा क्षेत्र के योगदान का अध्ययन करना।
3. भारत में रोजगार की चुनौतियां एवं अवसरों का अध्ययन करना।

@2025 Bihar Shodh Samaagam

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र मूलतः द्वितीयक समंको पर आधारित है इसमें अध्ययन के लिए वर्ष 1950–51 से 2024–25 के मध्य प्राप्त समंकों का संकलन आर्थिक सर्वेक्षण, आई.एम.एफ, विश्व बैंक एवं अन्य शोध–पत्र एवं पत्रिकाओं से किया गया है। समंको के विश्लेषण में प्रतिशत विधि एवं आवश्यकतानुसार अन्य विधियों का प्रयोग किया गया है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमबल की स्थिति– भारत में प्राथमिक क्षेत्र में 48.9 प्रतिशत श्रमबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है जबिक द्वितीयक क्षेत्र में 24.3 प्रतिशत तथा तृतीयक/सेवा क्षेत्र में 26.8 प्रतिशत श्रम बल कार्यरत है। भारतीय जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान 18 प्रतिशत है। जो की सबसे कम है। जबकि सबसे ज्यादा रोजगार 48.9 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ही प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र का योगदान जी.डी.पी. में 55 प्रतिशत है। जबकि वह मात्र 26.8 प्रतिशत ही लोगो को रोजगार प्रदान करता है। पीएलएफएस 2023–24 के अनुसार, कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रीणी बना हुआ है, जिसका हिस्सा 2017–18 में 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 46.1 प्रतिशत हो गया है। रोजगार में उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जिसमें विनिर्माण 12.1 प्रतिशत से घटकर 11.4 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 31.1 प्रतिशत से घटकर 29.7 प्रतिशत हो गई अतः स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र ही भारत के आर्थिक विकास का आधार है।

भारत में कार्यरत श्रम शक्ति की स्थिति 2011–12 (%)

क्षेत्र	कार्यरत श्रम शक्ति
प्राथमिक क्षेत्र/कृषि क्षेत्र	48.9
द्वितीयक क्षेत्र/ औद्योगिक क्षेत्र	24.3
तृतीयक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र	26.8

स्त्रोत– NSS 68 राउण्ड 2011–12

भारत में कार्य बल का क्षेत्रीय विवरण 2017–18 व 2023–24(%)

क्षेत्र	कार्यरत श्रम शक्ति(2017–18)	कार्यरत श्रम शक्ति (2023–24)
प्राथमिक क्षेत्र/कृषि क्षेत्र	44.1	46.1
द्वितीयक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र	12.1	11.4
तृतीयक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र	31.1	29.7

स्त्रोत – वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट 2023–24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय

भारत में जीडीपी एवं रोजगार के संबंध – सामान्यः जी.डी.पी. एवं रोजगार के मध्य धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। अर्थात जैसे–जैसे जी.डी.पी. में वृद्धि होती है। वैसे–वैसे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती जाती है। जी.डी.पी. में वृद्धि से विशेष रूप से उच्च– तकनीकी क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है। यदि जी.डी.पी. में वृद्धि रोजगार में बढ़ोत्तरी कर पाता है तो उसे समावेशी विकास की संज्ञा दी जाती है। भारत में भी समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया गया है। लेकिन वास्तव में भारत में पिछले दो दशकों का अनुभव दर्शाता है, कि तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद जो रोजगार के अवसर बनाये गए वो अपर्याप्त थे। जो कि अग्रसारणी से स्पष्ट है–

भारत में जी.डी.पी. वृद्धि एवं रोजगार वृद्धि

अवधि	जी0डी0पी0 वृद्धि	रोजगार वृद्धि
1972–73 से 1983	4.66	2.44
1983 से 1993–94	4.98	2.02
1993–94 से 2004–2005	6.27	1.84
2004–05 से 2009 से 2010	9.08	0.22
2010 से 2012	7.8	1.22

स्त्रोत– NSS 68 राउण्ड 2011–12 एवं महेन्द्र देव आलेख "रोजगार और आर्थिक वृद्धि" योजना अक्टूबर 2013

भारतीय अर्थव्यवस्था ने औसतन 6 से 7 फ़ीसदी की विकास दर हासिल की है, जो किसी भी लिहाज से खराब नहीं कही जा सकती । हालांकि यह विकास मुख्यतः सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के योगदान से प्राप्त हुआ है। यह विकास टिकाऊ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके आधार पर लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखना कठिन है। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को समावेशी कहा नहीं जा सकता इसे जॉब्लेस ग्रोथ का दौर भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च विकास दर के बावजूद रोजगार सृजन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, कि भारत में आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का तीव्र गति से विकास किया जाए इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और अतं में सेवा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां श्रम आधारित तकनीकी से उत्पादन संभव हो, वहां पूंजी आधारित तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसा की लेविस ने कहा है, कि जब प्रचलित मौद्रिक मजदूरी दर पर श्रम का आधिक्य हो तो उस मजदूरी दर पूंजी को उत्पादक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर वह वहीं काम करता है जो श्रम भी उतनी ही अच्छी तरह से कर सकता है। इस प्रकार के निवेश पूंजी पत्तियों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं लेकिन समाज की दृष्टिकोण से ये अलाभकारी होंगें, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, न कि उत्पादन।

संदर्भ :–

1. महेन्द्र देव, आलेख "रोजगार और आर्थिक वृद्धि" योजना अक्टूबर 2013
2. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एन.सी.ई.आर.टी. 2005
3. टरविंद कुमार सेन जनांकिकीय लाभांश या जनसंख्या अभिशाप योजना अक्टूबर 2013
4. वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट 2023–24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय
5. झिंगन एम0 एल0 एण्ड झिंगन बी0के0 (2012), विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन, वृंदा पब्लिकेशन प्रा0लि0
6. W.A. Lawis, "The Theory of Economic Growth" Oxford University Press London 1955
7. C.S.O.2012
8. Economics Survey 2024-25